



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (१)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

HB
- २८/१८१

क्र. ६१९] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर ५, १९८८/अग्रहायण १४, १९१०
No. 619] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 1988/AGRAHAYANA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह असाधारण के क्षम में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(विवेश कर प्रभाग)

नई दिल्ली, ५ दिसम्बर, १९८८

अधिसूचना

प्राय-कर

सा. का.नि. ११४६(प्र).—आय पर कर की वाबन वीहरे कराप्राप्ति का परिवर्तन और राजनियम अप्रवर्तन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा हिंज मेजेस्टी की नेपाल सरकार के बीच हुआ उपायद्रव्य करार, करार को प्रवृत्त करने के लिए उनको अपन-प्रपत्ती विधियों के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं के मूला होने पर और उक्त करार के अनुच्छेद २७ के अधीन दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा प्रतीक के लिए अधिसूचना आरी करने पर, तारीख १ दिसम्बर १९८८ को प्रवृत्त हो गया है।

इन, इब, केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, १९८१ (१९८१ का ४३) की बारा ९० और कंपनी (लाभ) अनिकर अधिनियम, १९८४ (१९८४ का ७) की बारा २४क द्वारा प्रवृत्त अधिनियमों का प्रयोग करो हुए।

निरेश वेती है कि उक्त करार के द्वारी उपर्यों को भारत के सभ में
प्रमाणी किया जाएगा।

प्राय पर करों के संबंध में
दोहरे कराप्राप्ति के परि-
हार और राजस्व के
अप्रवर्तन को रोकने के
लिए भारत गणराज्य की
सरकार तथा नेपाल
के द्वी ५ के सरकार के

वीच

करार

प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराप्राप्ति के
परिहार और राजस्व के अप्रवर्तन को रोकने
के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा नेपाल
के द्वी ५ के सरकार के वीच करार।

भारत गणराज्य की सरकार तथा
नेपाल के द्वी ५ के सरकार प्राय पर करों

के संबंध में दोहरे करारान के परिणाम और राजस्व के अपवर्कन को रोकने के लिए एक करार संपर्क करने की इच्छा से नोचे लिये अनुपार सहमत दुर्दृश्य है:

ग्रह्याय-I

करार का विषय-विवर

प्रत्यक्षेत्र 1

वैयक्तिक विषय-विवर

इह करार उत्तर अधिकारी पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अधिकारा द्वारा संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

प्रत्यक्षेत्र II

करार के अंतर्गत आने वाला कर

1. यह करार जिन करों पर लागू होगा, वे निम्नलिखित हैं—

(क) भारत के मामले में:

- (i) शायकर निम्नमें प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्यक्षीय उत्तर पर लगाया गया कोई भी अधिकार शामिल है;
- (ii) कांपी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अध्यक्षीय लगाया गया अतिकर; (जिन्हें इसके दाव भारतीय कर" कहा गया है)

(ख) नेपाल के मामले में:

- (i) शायकर अधिनियम, 2031 के अध्यक्षीय लगाया गया शायकर (जिसे हासके दाव "नेपाल कर" कहा गया है)।

2. यह करार किसी समरूप अधिका परिवर्तन के रूप में एक भासान उन करों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा पैरा 1 में उल्लिखित करों के प्रतिरिक्त, अधिका उत्तरके स्थान पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री-अपने करारान कानूनों में किए गये किसी सहस्रपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

ग्रह्याय-II

परिवायाएं

प्रत्यक्षेत्र-3

सामान्य परिवायाएं

1. इस करार में जब तक विषयगत पाठ में अधिका अपेक्षित नहीं हो:—

- (क) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से विषय-गत पाठ की अपेक्षा के प्रत्यक्षर भारत अधिका नेपाल अधिप्रेत है;
- (ख) "कर" शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के प्रत्यक्षर, भारतीय कर, अधिका नेपाल कर अधिप्रेत है, जिसमें वह यांत्रिक शामिल नहीं होगी, जो उन करों, जिन पर यह करार लागू होता है, के संबंध में किसी भी बड़ा अधिका गतिरोध के लिए देय होगी अधिका जो उन करों के संबंध में लागू भए अवैश्वर्य की शरण होगी;
- (ग) "अपित" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कांपी और कोई अधिका शामिल है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवरत करारान कानूनों के अधीन एक कर योग्य एकक के रूप में समझा जाता है;

(घ) "कांपी" शब्द से कोई भी ऐसा नियमित निवाय अधिका कोई प्रभ्य सत्ता अधिप्रेत है, जिसके संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवरत करारान कानूनों के अंतर्गत किसी कांपी अधिका अधिका नियमित निवाय के रूप में माना जाता है;

(ङ) "एक संविदाकारी राज्य का उदय" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उदय" शब्दों से क्रमा एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा संचालित कोई उदय और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उदय प्रभित है;

(च) भारत के मामले में "प्रभम प्राधिकारी" शब्द से अधिप्रेत है, विस संवालय (राजस्व विभाग) में केन्द्रीय सरकार अधिका उत्तरका प्रधिकार प्रतिनिधि; और नेपाल के मामले में महामहिम की सरकार, विस संवालय अधिका उत्तर कोई प्राधिकार प्रतिनिधि;

(छ) "राज्यिक" शब्द से कोई व्यक्ति जिसे संविदाकारों राज्य को राज्यिका प्राप्त हो तथा कोई विधिक उद्दिष्ट, भागीदारी और संस्था जो संविदाकारी राज्य में प्रवरत कानूनों से हम प्रकार की कांपी हैप्सित रखते हैं, अधिप्रेत है;

(ज) "भ्रस्तरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों का अधिप्राय एक संविदाकारी राज्य के किसी उदय द्वारा संकेतित नियो जायुगन द्वारा किसी परिवहन से है तै नियाएँ इसके कि जब यातायात इसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच हो चलाया जाता है।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए जाते का संबंध है, किसी शब्द का, जो इनमें परिवायित नहीं हुआ हो, विषयगत पाठ की अधिका अपेक्षा नहीं होते पर वहां अर्थ होगा, जो उम राज्य में उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत उपका गर्व है, जिन पर यह करार लागू होता है।

प्रत्यक्षेत्र 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोगनी के लिए "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से अधिप्रेत है, ऐसा कोई अपवित, विष पर उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत उपके अधिवक्ता, निवाय, प्रबंध स्थान अधिका इसके मिनी-कूनों किसी अर्थ मानवद के कारण कर लगाया जाना अपेक्षित हो।

2. जहां पैरा 1 के उपर्योगों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी हैप्सित निम्नानुसार नियिकत होगी:—

(क) वह उस राज्य का एक निवासी जाएगा, जिसमें उसका कोई स्थायी गृह हो; यदि उसके पास दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवासन्धृ है, तो वह उस राज्य का निवासी जाएगा, जिसमें उसकी आपिक गतिविधियों के निवास हैं;

(ख) यदि उसके पास किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवासन्धृ नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी जाएगा, जिसमें उपका व्यावहारिक आवास हो,

(ग) यदि उसका कोई व्यावहारिक आवास दोनों राज्यों में है अधिका उपमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस राज्य का निवासी जाएगा, जिसमें उपको आपिक गतिविधियों के निवास हैं;

(घ) विवादास्पद मामलों में संविदाकारी राज्यों के सभी प्राधिकारी मामले को परस्पर सहमति से हल करेंगे।

3. जहां पैराप्राप्त 1 के उपर्योगों के कानूनों से, किसी व्यक्ति से मिल कोई अपवित दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी

राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध-भविष्यता का स्थान निश्चित है।

प्रतिवर्ष ३

स्थायी संस्थापन

१. इस कारार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" ग्रन्थों से कारोबार का वह नियंत्रित स्थान अभिवित है, जहाँ से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अवश्य बंदन चालाया जाना है।

२. "स्थायी संस्थापन" ग्रन्थों में विशेषतः निम्नतिवान शामिल होते हैं:—

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शास्त्र;
- (ग) कोई कार्यक्रम;
- (घ) कोई कारबाहा;
- (ङ) कोई कर्मग्राम;

(ज) कोई धारा, कोई तेज अवश्य ऐस कूद, कोई ज्वान अवश्य प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण का कोई अन्य स्थान;

(झ) कोई भवन-स्थल अवश्य निर्माण अवश्य एवं विनायक विनायक के द्वारा एवं विनायक वारह महानों की किसी अवधि के द्वारा न १८३ दिन से अधिक की अवधि अवश्य अवश्य अवधियों के लिए बदलते हैं;

(झ) किसी उद्यम द्वारा कर्मवाहिनी अवश्य अवश्य कामिकों की गार्फ़ से वार्षिक प्रदान करना जहाँ देश के द्वितीय एवं कार्यक्रमाप वारह महानों को किसी अवधि के द्वारा न १८३ दिन से अधिक की अवधि अवश्य अवश्यियों के लिए बदलते हैं;

३. इस प्रतिवर्ष में पूर्वजीवी उद्यमों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" के अन्तर्गत नियंत्रित का शामिल नहीं माना जाएगा;

(क) उद्यम के माल अवश्य वाणिज्यिक वस्तुओं के माल अंतर्राष्ट्रीय अवश्य ग्रहण के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का उपयोग;

(ख) केवल अंतर्राष्ट्रीय अवश्य के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अवश्य वाणिज्यिक वस्तुओं के स्टाक का रख-रखाव;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के लिए से उद्यम के माल अवश्य वाणिज्यिक वस्तुओं के स्टाक का रख-रखाव;

(घ) उद्यम के लिए केवल माल अवश्य वाणिज्यिक वस्तुओं को खरीदने अवश्य सूचना एकद करने के उद्देश्य से कारबार के किसी नियंत्रित स्थान का रख-रखाव;

(ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अवश्य सहायक किस्म के किसी अन्य कार्यक्रमाप भाव के प्रयोजनार्थ कारबार के किसी नियंत्रित स्थान का रख-रखाव।

४. पैराप्राफ १ तथा २ के उद्यमों के होते हुए भी जहाँ कोई अविक्षित, जो स्वतंत्र सिवित के किसी एजेंट, त्रिम पर पैराप्राफ ५ सागू हीता ही से भिन्न हो, एक संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तथा उसके पास उद्यम की ओर से संविदाएँ सम्बन्ध करते का प्राधिकार ही तथा वह उसका नियंत्रित रूप से प्रयोग करता है, वह उन उद्यम का उन्नत राज्य में उन कार्यक्रमापों के संबंध में एक स्थायी संस्थापन होता माना जाएगा जो वह अविक्षित उद्यम के लिए करता है जब तक कि ऐसे अविक्षित के कार्यक्रमाप उक्त उद्यम के लिए माल अवश्य कियितक बनने को बताएँ तब ही सोमेन नहीं हों।

५. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में भाव इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होता नहीं माना जाएगा जि वह वह दूसरे राज्य में फिरी द्वारा, सामान्य कार्यक्रम एजेंट अवश्य स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम कारोबार करता है, वश्वते ऐसे अविक्षित अवश्य कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि जब ऐसे एजेंट के कार्यक्रम पूर्णतः अवश्य लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किये गये हों तो उसे इस पैराप्राफ के अधिकार के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा।

६. इस सत्र से कि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की नियासी है, किसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अवश्य उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की नियासी है, अवश्य जो उस दूसरे राज्य में (वह स्थायी संस्थापन के माध्यम से अवश्य अवश्य) कारबार चलाती है, इन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरे कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

भ्राय-३

भ्राय का कराधार

प्रतिवर्ष ६

प्रब्रत सम्भवि से भ्राय

१. एक संविदाकारी राज्य के किसी नियासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्भवि (जिसमें कृषि अवश्य वानिकी से प्राप्त भ्राय भी शामिल है) से प्राप्त भ्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लाया।

२. "अचल सम्भवि" पक का भ्राय वही होता है, जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका भ्राय है जिसमें नंबिंग सम्भवि स्थित है। इस पक में किसी भी हालत में ये रामिल होते हैं—अचल सम्भवि के उपसाधन के रूप में सम्भवि, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और चपलकर, ऐसे अविक्षित जिन पर भूसम्भवि संबंधी सामान्य कानून के उपर्यंग लागू होते हैं अचल सम्भवि को भोगी के अविक्षित और वानिकी भपडार, जो उस तथा अवश्यिक संचालन के संचालन के लिए इस्या संचालन के अधिकार के प्रतिकल के रूप में परिवर्तीय अवश्य नियंत्रित अवश्यियों के अधिकार। जनवान जीकाएं तथा वायुवान अचल सम्भवि नहीं माने जाएंगे।

३. पैराप्राफ १ के उपर्यंग अचल सम्भवि के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे कियाये पर देने अवश्य किसी अन्य प्रहार के उपयोग से होने वाली भ्राय पर भी लागू होते हैं।

४. पैराप्राफ १ तथा ३ के उपर्यंग किसी उद्यम की अचल सम्भवि से अविक्षित भ्राय पर और उपर्यंग अविक्षित सेवाओं के निपाइन के लिए प्रयुक्त अचल सम्भवि से अविक्षित भ्राय पर भी लागू होते हैं।

प्रतिवर्ष ७

कारबार से भ्राय

१. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारबार नहीं करता है। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लायेगा किन्तु यह कर केवल उतने बंदा पर लायेगा जितना कि उस स्थायी संस्थापन के कारण हुआ हो।

२. पैराप्राफ ३ के उपर्यंग के अवीन रहते हुए, जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारबार करता हो, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में, उस स्थायी संस्थापन को वह लाभ प्राप्त हुआ समझा जाएगा।

जिसके प्राप्त होने की उस स्थिति में धरेखा रही जब वह उन्हीं धरण कीसी ही परिस्थितियों में उन्हीं या ऐसे ही कार्यों में जगा हुआ छोई पिल्ल और उसके उदयम होता और उस उदयम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका वह स्थायी संस्थापन है।

3. (क) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते में उदयम के ऐसे खातों की कटौती की अनुमति होती जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजन के लिए किए गए हों जिनमें केवल कार्यालयी तथा सामान्य प्रशासनिक खाते शामिल हों जाहे वे खाते उस राज्य में किए गए हों, जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है धरणा अन्यत जिए गए हों जो कि उस विविधकारी राज्य के कानूनों के उपर्योगों के अधीन अनुमत्य है जहाँ कि स्थायी संस्थापन स्थित है।

(ब) तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा उदयम के प्रधान कार्यालय धरणा उसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेन्ट्स धरणा धरण अधिकारों के प्रयोग के प्रतिक्रिया में रायलिट्यों, फैस धरणा इससे मिलती-जुलती धरण विविधों धरणा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए धरणा प्रबंध व्यवस्था के लिए कर्मसूल के रूप में धरणा कार्यालय के पेटेन्ट्स धरणा अन्य अधिकारों के उपर्योग के प्रतिक्रिया में रायलिट्यों, फैस धरणा इससे मिलती-जुलती धरण विविधों धरणा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए धरणा प्रबंध व्यवस्था के लिए कर्मसूल के रूप में धरणा कार्यालय उदयम के प्रधान कार्यालय धरणा उसके किसी अन्य कार्यालय को जगार दो गई बनराति पर धरण के रूप में प्रवालित रकम (जो वास्तविक खातों की प्रतिपूर्ति से मिल हो) को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

4. जहाँ तक किसी विविधकारी राज्य में, उदयम के कुल लाभों को उसके विविन्न भागों के प्रति संविधान के कारबार पर किसी स्थायी संस्थापन के कारबार माने जाने जाने जाने लाभों को निश्चित करते की प्रया हो, वह पैराग्राफ 2 की कोई भी धरणा उस संविधानकारी राज्य को ऐसी प्रविदि। विविधान पद्धति से, कर लगाए जाने जाने लाभों को निश्चित करते से प्रतिवधित नहीं करें, तथापि, उक्त संविधान पद्धति ऐसी होगी, कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के मनुसार होना।

5. कोई साथ केवल इस कारबार कोई स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उदयम के लिए माल या वाणिज्यिक बस्तुएँ आयी हों हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारबार हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्णनियर्थ उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत कोई उचित तथा पर्याप्त कारबार नहीं हो।

7. जहाँ लाभों में धाय की ऐसी भवि सामिल हों जिन पर इस कारबार के अन्य अनुच्छेदों में धरण से कारबार किया गया है, उस स्थिति में उत्तर अनुच्छेदों के उपर्योग पर इस अनुच्छेद के उपर्योगों का कोई प्रभाव नहीं पहेजा।

अनुच्छेद 8

धाय परिवहन

1. किसी संविधानकारी राज्य के उदयम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायान में विमान परिवालन से प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही सामान्य जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपर्योग किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार धरण किसी बहुराष्ट्रीय प्रवालन प्रभिकरण में धाय लेने से प्राप्त लाभों पर भी सामान्य होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायान में विमान परिवालन से संबंधित निषियों पर धाय को ऐसे विमान परिवालन से प्राप्त धाय/लाभ माना जाएगा और ऐसे धाय के संबंध में धारा 11 के उपबन्ध सामान्य नहीं होंगे।

4. "वायुयान परिवालन" पद का अर्थ यह होगा--वायुयान के मालिकों या पट्टेदारों धरणा धरणेताओं 'वार्टेस' द्वारा धायियों, डॉक, पशुधन या माल का वायुयान से परिवहन का धायावार, जिम्में धाय उदयमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की विक्री, वायुयान का अनु-संचिक पटा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई भी अन्य कार्य-कालाप शामिल है।

अनुच्छेद 9

संबंध उदयम

जहाँ :

(क) एक संविधानकारी राज्य का उदयम दूसरे संविधानकारी राज्य के उदयम के प्रबंध, नियंत्रण धरणा पूँजी में प्रत्यक्षतः धरणा प्रत्यक्षतः धाय लेता है, तथा

(ब) वे ही व्यक्ति एक संविधानकारी राज्य के उदयम और दूसरे संविधानकारी राज्य के उदयम के प्रबंध, नियंत्रण धरणा पूँजी में प्रत्यक्षतः धरणा प्रत्यक्षतः धाय लेते हैं, और दोनों ही धरणस्थानों में, दोनों उदयमों के बीच उनके वाणिज्यिक धरणा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी धरणा लगायी जाती हों, जो उन शर्तों से भिन्न हों और स्वतंत्र उदयमों के बीच रखी जाती हों तो ऐसा कोई भी साध, जो उन शर्तों के नहीं होने की दशा में उन उदयमों में से एक उदयम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, तो वह साध उस उदयम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तदनुसार कर सकेगा।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. जो कमनी एक संविधानकारी राज्य का निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविधानकारी राज्य के निवासी को धरा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराओय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविधानकारी राज्य में भी, जिसकी लाभांश प्रदा करने वाली कमनी निवासी है और उस राज्य के कानून के अनुसार सार्वधेय होंगे, किन्तु यदि पाने वाला लाभांशों का हितभानी स्थानी हो तो इस प्रकार साधार्य जाने वाला कर--

(क) लाभांशों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाही कमनी है जिसके पास लाभांश देने वाली कमनी के भेयरों के कम-से-कम इस प्रतिशत से अधिक होंगे;

(ख) अन्य सभी भागों में लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाही।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कमनी के कारबार पर कोई प्रभाव नहीं आलेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में धाय प्रमुखता "लाभांशों" पद का अभिव्यक्त शेवरी प्रधान कोई धरण धरणियों से प्राप्त धाय से है जो क्रम-दर्शने नहीं होंगे,

सामने में आगिराह हों, तथा अस्थि निरनित अधिकारों से प्राप्त आप से है जिस पर उसी प्रकार कर लगाया जाता है, जिस प्रकार कि उस यात्रण के करावान कानूनों द्वारा शेरों से प्राप्त आप पर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली काम्पनी निर्वाचनी है।

4. पैरापाक 1 और 2 के उत्तरवर्ती उम स्थिति में लाभू नहीं होते, यदि लाभार्थी का हितभारी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभार्थी अश्व कर्त्ता वाली कम्पनी निवासी है, वहां स्थित एक स्वार्थी संस्थान के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उम दूसरे राज्य में स्थित एक निविच्छन स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं रक्षण करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभार्थी की व्यापारी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थाई संस्थान अन्या निविच्छन स्थान से प्रभावीरूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में, यथा स्थिति, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 13 के उत्तरवर्ती लागू होते।

5. जहाँ कोई कम्ननी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ भव्यता आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य कम्ननी द्वारा भव्य किए गए लाभों पर किसी भी प्रकार का कर गही लगा सकेगा, केवल उस सीमा को छाड़कर जहाँ तक कि ऐसे सामांज उस दूसरे राज्य के निवासी को यथा किए जाते हैं अर्थात् जहाँ तक कि वह धारणाधिकार जिसके संबंध में लर्भाणों को अदायगी को जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन भव्यता किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, और न ही कम्ननी के अवितरित लाभों पर अवितरित साम संबंधी कर भगायां जाएंगा, वाहे अश्व किए गए लाभांश भव्यता अवितरित साम पूर्ण रूप से अर्थात् अवितरित रूप से इस प्रकार के दूसरे राज्य में उत्तम होने वाले साम भव्यता आय के रूप में ही हों।

मनुष्येव 11

म्यामि

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्यापक पर उस दूसरे राज्य में कर सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस सविवाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उच्चभूत होता है किंतु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितवार्गी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रमारित कर की राशि व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

तथापि, यह यह है कि जहाँ व्याज वास्तविक बैंकिंग व्यापार चलाने वाले उस बैंक को दिया जाता है, जो दूसरे संविवाकारी राज्य का निवासी है और जो व्याज का हितमार्गी स्वामी है, वहाँ जिस संविवाकारी राज्य में व्याज उद्भूत होता है उस राज्य में प्रभारित कर व्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।

3. ऐतापाक 2 के उपर्याप्ति के होते हुए भी, किसी संविवाकी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याप्ति पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी वरतों पह निम्नलिखित दारा प्राप्त किया गया हो तथा हिंदमारी रूप से रखा पाया हो :

(i) दूसरे संविधानार्थी राज्य की सरकार, कोई राजनीतिक दबाव प्रभाग अधिकार कोई स्थानीय प्राधिकरण, अधिकार (ii) दूसरे संविधानार्थी राज्य का संसद नहीं।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “व्याज” शब्द से अधिकतेत है प्रस्तेक प्रकार के अप्प संबंधी वार्तों से प्राप्त याय, वाहे वे बंधक द्वारा प्रतिबृत्त हों यथा नहीं और वाहे अप्पदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो यथा तरीं और विशेष काम में सहायता की प्रतिमितियों से प्राप्त

आय-बंधवत्रों प्रथमा अरण्यत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिपूर्तियों, बंधवत्रों प्रथमा अरण्यत्रों से संबंधित लाभांश और पुरकार शामिल हैं। वित्तम् से की नई दरायगी के लिए अत्रीदण्ड संबंधी प्रवारों को इस अनुच्छेद के प्रयोगान्वय व्याज नहीं माना जाएगा।

5. पैरपाक 1 और 2 के उत्तरवेद उत्तर स्थिति में नामूनहीं होंगे, यदि व्याज का त्रिपलाती स्थानी, जो एक सविदाकारी राज्य भी निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्तम हृष्टा हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी सत्याग्रह के माध्यम से कारोबार चलाता है प्रथम उस दूसरे राज्य में वहाँ स्थित एक निविलन स्थान से स्वतंत्र वैदिक सेवाएं सम्पन्न करता है, और जिस ज्ञान-संवेद के बारे में व्याज भक्ता किया जाय हो वह इस प्रकार के स्थायी सत्याग्रह प्रथम निविलन स्थान से प्रवासी रूप से संयंत्रित है। ऐसे भासने में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 13 के प्रवृत्ति, जैगा यी मामला हो, लागू होंगे।

६. ध्याय विसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ भाना जाएगा, जब ध्याय प्रारंभ हो वाले स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभावा, कोई ध्यानीय गाविकरण अवशा निरासी हो। विन्तु जहाँ ध्याय भरा जरने वाले विनियोग, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अवशा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थान अवशा निरित स्थान है जिसके भवें में वह बहुत निया जाया या, जिस पर ध्याय की अवशायी की जाती है, और इस प्रकार का ध्याय इस प्रकार के स्थायी संस्थान अवशा निरित स्थान प्रारंभ वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ध्याय उन संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ भाना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थान अवशा निरित स्थान दिया है।

७. जहाँ ब्याज अवाकर्षण स्था उनके हिन्दागी स्थानी के बोच अथवा उन दोनों और फिसी अन्य व्यक्ति के बोच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण ब्याज की गई ब्याज की रकम, उन अद्यतनोंवें को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अश की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अद्यतनों और हिन्दागी स्थानी के बोच महसूल हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपर्युक्त केवल अतिम वर्णित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामलों में अवायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपलब्धों का मन्त्रक अनुपलन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के मनसार कर लगाया जाना।

મનભૂત્ય 12

रायलिट्या

1. एक भवित्वाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के नियासी को अदा की गई रायलिटियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी रायलिट्टिंगों पर उस संविधानकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उसी राज्य के कानून के अनुसार, कर बगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायलिटी का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार बगाया गया कर ऐसी रायलिट्टिंगों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से प्रतिक महीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्ति "रायलिट्डों" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक भ्रष्टवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचित्र फिल्में, भ्रष्टवा रेडियो भूरखर्चन प्रसारण के लिए प्रयुक्ति फिल्में भ्रष्टवा देखें शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, भ्रष्टवा प्रयोगाधिकार के प्रयोग के प्रतिकल के रूप में डिजाइन भ्रष्टवा माइल, प्लान, गुप्त फारमला भ्रष्टवा प्रक्रिया के प्रयोग, भ्रष्टवा औद्योगिक, वाणिज्यिक भ्रष्टवा वैज्ञानिक उपस्करण के प्रयोग के लिए भ्रष्टवा प्रयोगाधिकार के प्रयोग के लिए, भ्रष्टवा औद्योगिक, वाणिज्यिक भ्रष्टवा वैज्ञानिक भ्रम्मवद से संबंधित ज्ञानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की भ्रायरी सम्प्रीत है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में नागू नहीं होती यदि रायलिट्डों का द्वितीयनी स्थानी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायलिट्डों उद्भूत होती है, वहाँ स्थित किसी स्थानी संस्थापन के माध्यम से या वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार या संपत्ति के नियंत्रण में रायलिट्डों अधा की जाती है, वह ऐसे स्थानी संस्थापन या निश्चित रथान के गायत्र प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या 13 के उपर्युक्त जैसी भी स्थिति हो नागू होती।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायलिटी तब उद्भूत मानी जाएगी, जब रायलिटी अधा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाव, कोई स्थानीय प्राधिकारण हो या कोई निवासी हो। तथापि, जहाँ ग्रामली अधा करते वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी है या नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थानी संस्थापन अधा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके रावण्डे में रायलिटी अधा करने की देनदारी उद्भूत हुई ऐसी रायलिटी ऐसी स्थानी संस्थापन द्वारा अधा निश्चित स्थान द्वारा वहाँ की जाती हो, तो ऐसी रायलिटी उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थानी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित है।

6. यहाँ अधाकर्ता और हितभागी स्थानी के बीच अधिकार उम्मीदों के तापा किसी अन्य अविनित के बीच विदेश प्रकार का संबंध होने के कारण, रायलिटी की रायित उपयोग, अधिकार और सूचना को प्राप्ति में रखते हुए, जिसके लिए इसे आदा किया जाता है, उस रायित ने बहु जाती है जो इस प्रकार का संबंध न होने की स्थिति में अदाकर्ता और द्वितीयनी स्थानी द्वारा तथा की गई होती, तो वहाँ इस प्रत्यक्षित के उपर्युक्त केवल अन्तिम वर्णित वर्ष पर ही सागू होते हैं। ऐसे मामले में, अधिक अधा की गई अधा पर करार के अन्य उपर्युक्तों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा ध्यावसायिक सेवाओं अथवा उम्मी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों द्वारा प्राप्त आय पर निम्नलिखित परिवित्तियों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है तब उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा उकती है;

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निपादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित रथान स्थिति रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उनी आय पर कर लगाया जा रखेगा जिसने उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा उकती है;

(द) यदि इसकी दूसरे संविदाकारी राज्य में उपर्युक्त की अवधि या अधिकारी निवासी संगत “पूर्ववर्ती अर्थ” अधा “आय के अर्थ” में, जैसी भी रिप्टिंग हो, कुल 183 दिन अधा उससे अधिक हो, उस मामले में, तो आय के केवल उन्ने आग पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा रखेगा जो उस दूसरे राज्य में निलंबित उनके कार्यकलापों से उसे प्राप्त होती हो।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैयक्तिकों, माहित्यक, कलानक, शैक्षिक अध्ययन संबंधी कार्यकलाप तथा विकासकों, शस्त्र-योगित्सकों, वकीलों, ईजीनियरों, वास्तुविदों, इत्यत्रिक्तकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 14

परामित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, और 20 के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, भजद्वारी सथा इसी प्रकार के प्रत्येक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि नियोजन किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन इस प्रकार किया जाता है तो ऐसे परिवर्तिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपर्युक्तों के होने द्वारा भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त परिवर्तिक पर केवल प्रथमोलिंगित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत “पूर्ववर्ती अर्थ” अधा “आय के अर्थ” में जैसा भी सामाजिक हो, कुल मिशनकार 183 दिन से प्रान्तिक की अधा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मीजूद रहा हो; तथा

(ख) पारिवर्तिक, ऐसे नियोजन द्वारा या उसकी ओर से अधा किया जाता है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं हो; और

(ग) पारिवर्तिक, किसी ऐसे रायावी ग्रस्तापन या निश्चित स्थान द्वारा बहुत नहीं किया जाता हो जो नियोजन का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपर्युक्तों के होने हुए भी एक नविदा-कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्रत्यन्तराष्ट्रीय वातावाहन में पर-भालित किसी हवाई वाहन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त परिवर्तिक पर कर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 15

निवेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के मिदेशक मण्डल के सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, ग्राम की गयी निवेशक की फीस नथा इसी प्रकार की अन्य अधा-गियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-16

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

अनुच्छेद 13 और 14 के उपर्युक्तों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे पिंडेट, खलचिंह, रेडियो अधा दूरदर्शन कलाकार या संसीतकार अधा विलासी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. जब किसी मनोरंजनकर्ता अधा विलासी द्वारा किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में अपनी इस प्रकार की हैसियत से प्राप्त आय मनोरंजनकर्ता अधा विलासी को प्राप्त नहीं हो, अर्थात् किसी अन्य व्यक्तिकों को प्राप्त होती हो तो अनुच्छेद 7, 13 और 14 के उपर्युक्तों के होने हुए भी, उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिस राज्य में मनोरंजनकर्ता अधा विलासी द्वारा ऐसे कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराप्राप्त 1 के उपबंधों के होते हुए भी, जिसी मानोरक्षकली प्रथा दिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार हो किए गए उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में केवल प्रथमोन्सिलिंग संविदाकारी राज्य में ही कर सकता जा सकेगा, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उन कार्यकलापों को प्रथमोन्सिलिंग संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निषियों से, जिसमें उसके राजनीतिक उप-प्रभागों से से कोई उप-प्रभाग, प्रथम स्वामीय प्राधिकरण भी शामिल है, पूर्णतः अधिकारी अंशतः सहायता दी जाती है।

4. तीरायाक 2 और अमृष्टलेद 7,13 और 14 के उपर्याधों के होते हैं भी, जहां मनोरंजनकारी प्रथां विलासी हारा भागी इन प्रकार की हृसियत से किसी संविदाकारी राज्य में किए गए वैश्विक कार्यकलापों से प्राप्त प्राप्त रवर्य भवीरंजनकारी प्रथां विलासी को प्राप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ऐसे मामले में उस प्राप्त पर उस हृसियत में फेशल तूसरे संविदाकारी राज्य ने ही कर लगाया जा सकेगा मर्दि उस अन्य व्यक्ति को तूसरे संविदाकारी राज्य की सांवर्जनिक नियमों से जिम्मे उसके राजनीति उप प्रभागों में से कोई उप-प्रभाग भा स्थानीय प्राधिकरण सामिल है, पूर्णतः प्रथा औरतः सहायता वी जाती है।

अरमाणुलेद १७

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेशान

1. (क) किसी संविवाकारी राष्ट्र, अथवा उसके राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्रधिकरण द्वारा व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग या प्रधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में पेश से भिन्न भाव किए, रुपारित्रिक पर कर केवल उस राज्य में ही संगेना

(श्र) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी स्थिति में ही बार लग जाएगा, भवित्वे प्राप्त दूसरे राज्य में की जाती है और व्यष्टि उस राज्य का निवासी है, जो :-

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक हो; अध्या

(ii) सेवाएं अधिकरण मात्र के प्रयोगनार्थ उस राज्य का निव से नहीं ज्ञान।

2. (क) विसी सविदाकारी राज्य अधिकारी उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अधिकारी व अन्य प्रधिकारण के लिए की गयी सेवाओं के सम्बंध में उस सविदाकारी राज्य अधिकारी राजनीतिक उप-प्रभाग अधिकारी प्रधिकारण द्वारा मूलित नियमों में से किसी व्यक्ति को अदा की गयी विसी वी पैसें व पर व्यक्ति उस राज्य में ही कर सकेगा।

(ख) तापापि, ऐसी पेशन पर उम स्थिति में केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर सकेगा यदि व्याप्ति उस राज्य का आवासी हो जो राष्ट्रिक हो।

3. अन्तिम 14, 15 और 16 के उत्तराधि, किसी संविदाकारी राज्य या उसके गजनीतिक उप-प्रधान अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अलाये जा रहे कारोबार के दारे में की गयी संखाओं के संबंध में पारिषदीक और पंथन पर साधु होंगे।

अनंच्छ्रद्ध 18

गैर सरकारी पेशन और वाषिकिय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी नियामी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के बोतो से प्राप्त अनुच्छेद 17 में उल्लिखित पेंशन से नियमित किसी पेंशन अधिकारी किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही लगाया जाए।

2. "ऐक्य" शब्द का अर्थ उस सिद्धांत कापिक मुश्तान से है कि जो विगत में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में ग्रथवा सेवाओं के निष्पादन के द्वारा नारीरिक चौट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. "वायिकी" एवं का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त हथा पूरे प्रतिकृत के लिए अदायगिया करने के लिए दायित्व के अधीन जीवन पर्यन्त अथवा विनिर्विट अथवा निश्चय समायावधि के द्वारा उल्लिखित समय पर मावधिक रूप से देय हो।

अनुच्छेद 15

विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षकों द्वारा प्राप्त आदायगिमि-

(क) उम दूसरे संविधानारो राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोगशार्थी उससे को गई अदाय गिरा : राण

(क) उस तृतीय सवियाकारी राशि में किसी "विवरण वर्ष" अध्यवाद "प्राय वर्ष" जैसी शी रिपब्लिक हो, में रोजगार से प्राप्त विवरणिक पर जो 18,000 रु. (भारतीय मुद्रा) अध्यवाद नेपाली मुद्रा में उसके सममुद्र्य से अधिक न हो, लगते कि ऐसा नियोजन उसके अध्यवाद से सीधे संबंधित हो अध्यवाद उसके भरण पोषण के प्रयोगजारी शक्ति किया गया हो।

२. इस अनुष्ठान का लाभ निवेद ऐपी अधिकारी के लिए मिलेगा जो प्रारंभ की एई शिक्षा अभ्यास प्रशिक्षण को पूरा करने हैं लिए उचित अध्ययन भागारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में किसी न्यूनिट को उत्तरके इस दूसरे संविदाकारी राश्य में प्रयोग वार उभे पृष्ठने की तारीख से लगातार सीन वर्ष में अधिक अधिकारी के लिए अनुष्ठान का लाभ प्राप्त मही होगा।

प्रान्तरालेख 20

प्राधानिकों, प्रधानिकों तथा गोप छात्रों द्वारा प्राप्त धरापगिया

1. किसी प्राय्यापक अधिकारा अध्यापक को, जो दूसरे मंविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल में अधिकारा दूसरी मास्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन अधिकारा शोध कार्य के लिए अधिकारा दोनों को प्रयोजनार्थ उस दूसरे राजिदाकारी राज्य में पहुँचने से बुरत फूले मंविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है अधिकारा था, उस दूसरे राज्य में पहुँचने की तारीख में दो वर्षों से भ्रन्तिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अधिकारा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उग दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छट प्राप्त होगी ।

2. यह भनुष्टेद उम शोध कार्य तो न्रात्म भाष्य पर लागू नहीं होगा। यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी अधिकारियों के मित्री लाग्म के लिए किया जाता है।

3. इस प्रमुख्यादेता अनुच्छेद 19 के प्रयोजनार्थे 'किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह "पूर्ववर्ती वर्षे" अथवा "माय वर्षे" में यथा विविध, वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा "पूर्ववर्ती वर्षे" अथवा माय वर्षे के तुरत पहले उस संविदाकारी राज्य का विवरण हो।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यता ग्राव्य" संस्का का द्वाये एक ऐसी संस्का से है जिसे इस संबंध में संविधान संविदाकारी राज्य के नकाम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गई है।

अनुच्छेद 21

मान्य द्वाय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के प्रयोग रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की ऐसी मर्दें, जहाँ कहीं वे उद्भूत होती हों और जिन पर इस करार के प्रूपोंके अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विवार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में करावधी होती।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिमापित अधिक सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होती, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में, वही स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वही स्थित किसी नियित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं नियावित करता है, तथा ऐसा अधिकार अवश्य मन्त्रित त्रिभूमि मन्त्रकर्त्ता भी ऐसी आयकर्ता की जाती है, ऐसी स्थायी संस्थापन अथवा नियित आवाहन से प्रभावी रूप से स्वतंत्र है। ऐसे आमतौरे में अनुच्छेद 7 अवश्य अनुच्छेद 13 के उपबंध जैसी भी स्थित होती है, लागू होती।

आय 4

दूहरे कराधान के प्रयोगकरण के बारे प्रश्नाली

अनुच्छेद 22

दूहरे कराधान का प्रयोगकरण

संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून उन संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के मामलों में लागू होने लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर अहाँ इन करार में उनमें विवरीत कोई उपबंध किए जाते हैं। जहाँ आय पर दोनों राज्यों में कर लगता हो वहा इन अनुच्छेद के प्रयोगान्वयन दूहरे कराधान से लाभ प्रदान की जाएगी।

2. नेपाल से आवाह नियी लेने में संदेश कर को नेपाली कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने के संबंध में नेपाल के कानून के उपबंधों के अध्यवधि (जो इसके मान्यता सिद्धान्तों को प्रभावित नहीं करते), भारत के कानून के अन्तर्गत और इस करार के उपबंधों के अनुसार, गारान में स्त्रीों से प्राप्त आय के सबव भी प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा द्वेष भारतीय कर आय की उम्ही मर्दों के संबंध में जिन पर भारतीय कर की गणना की जाती है, संगतियों की गई नेपाली कर की रकम के प्रति अभा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी।

3. पैराग्राफ (2) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए शब्द "द्वेष भारतीय कर" में वह गणना शामिल समझी जाएगी जिसकी नियन्त्रित विशेष प्रोत्साहन उत्तरांश द्वारा कर में कटौती की जाएगी—

(i) भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की आय 10(4), 10(4क), 10(6) (ii), 10(5) (iv), 10(28), 10क, 32क, 33क, 80जज, 80जनर, 80स, और 803;

(ii) कोई अन्य उपबंध जो आद में कर से ऐसी कटौती प्रदान करने के लिए अधिनियम। किस जाएग, जिस पर संविदाकारी राज्यों के सदम प्राधिकारी आधिक विकास के प्रयोजनों के लिए सहमत हो।

4. भारत से बाहर किसी लेन में द्वेष की भारतीय कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने के संबंध में भारत के कानून के उपबंधों

के अध्यवधि (जो इसके मान्यता सिद्धान्तों को प्रभावित नहीं करते) नेपाल के कानून के अध्यवधि और इस करार के उपबंधों के अनुसार नेपाल में स्त्रीों से प्राप्त आय के संबंध में प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा द्वेष नेपाली कर, आयकर की उम्ही मर्दों के संबंध में जिन पर नेपाली कर की भारतीय कर की गणना के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी।

बल्कि ऐसी द्वेष द्वारा द्वेष भारतीय कर (ऐसी द्वेष द्वारा की स्वीकृति देने से पहले की गई गणना के प्रत्यक्षतः) से अधिक नहीं होती जो कि नेपाल में स्त्रीों से प्राप्त आय के विनियोज्य होती। तथापि, जहाँ पर ऐसा निवासी वह कम्ती हो जिसके द्वारा भारत में अतिकर द्वेष हो, वह भारत में कम्ती द्वारा द्वेष आयकर के प्रति उपर्युक्त जमा की स्वीकृति प्रष्टमतया भी जाएगी और यदि कोई शेष द्वेष द्वारा द्वेष होती, तो उसके लिए कम्ती द्वारा भारत में द्वेष अनिकर के प्रति स्वीकृति दी जाएगी।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के प्रयोजनार्थ "संदेश नेपाली कर" में ऐसी कोई रकम शामिल की गई समझी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए नेपाली कर के रूप में संदेश हो गई होती परन्तु उस वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए नियानुसार कर में भी गई छट अथवा उसमें भी गई कटौती के कारण ऐसा नहीं हुआ।

(क) नेपाल आयकर अधिनियम, 2031 (1974) की भाग 42 के उपधारा (2), जिस हव तक यह प्रवृत्त थी और तब से उस करार पर हम्माक्षर होने की तारीख तक संशोधन नहीं किया गया हो या उसमें मामूली-मा संशोधन किया गया हो ताकि उनसे उसके मान्यता स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हो; अथवा

(ख) कोई अन्य उपबंध जिसे कर से छट प्रदान करने प्रथवा उसमें कटौती करने के बाद बनाया जाए, जिसके लिए मक्तम प्राधिकारियों में सहमति होती है और जो काफी हद तक उनी प्रकार के स्वरूप का हो, यदि ऐसे उपके परवात संशोधन नहीं किया गया हो या इनमें मामूली-मा संशोधन किया गया हो ताकि इससे उसके मान्यता स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

6. जहाँ इस करार के प्रयोजन, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अन्य संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय के संबंध में उम संविदाकारी राज्य में कर से छट दी जाती है, तब प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य उस अधिक भी शेष आय पर कर की संगणना करने समय कर की वह दर लगाएगा जो उस अथवा में लागू होती यदि इस करार के अनुसार कर से छट प्राप्त आय पर कर से छट प्राप्त नहीं होती हो।

अध्याय 5

विशेष उपबंध

अनुच्छेद 23

समव्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के शास्त्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई करार न अथवा न उसमें कोई प्रयोजन लागू नहीं होती, जो उस कराधान से और उस संबंधित प्रयोजनों से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक हो, तथा उसके अधिकारी अपेक्षाएं जो उस दूसरे राज्य के शास्त्रियों पर एक-समान परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उपकर के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उच्चमों पर एक-समान

परिस्थितियों के अधीन समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कानून से भ्रमित करने का अनुकूल होता है।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी वात का यह अर्थ नहीं सायाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के अधिकारियों को जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की अवितरण छूट, राहत, कटीतियों तथा घटीतियों मेंजुर करके, जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे अधिकारियों को उपलब्ध हैं जो वहां के निवासी हैं, उपकृत करना है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उदाहरण पर, जिसके पूँजी पूर्णतः अधिकारी बंधन: इससे संविदाकारी राज्य के एक अधिकारी एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अधिकारा प्रत्यक्ष स्वामित्व में अधिकारा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई करावान अधिकारा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कांगड़ान से अधिकारा लत्संबंधी किसी भी अपेक्षाओं से अधिकारा अधिकारा कृष्ण अधिकारी भारतपूर्ण है जो प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य के अन्य समस्त उदाहरण पर एक-समान परिस्थितियों के अधीन लगाई जाती हैं।

३ इस भनुष्ठोद में "कराधान" गद्य का ग्रन्थ उत करों से है जो इस कथार के विषय है।

अनुष्ठान 24

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझे कि एक अवयवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप दृष्ट पर बहु कर लगाया जाता है अवयवा लगाया जाएगा, जो प्रस्तुत कराए के प्रस्तुत नहीं है तो उन राज्यों के राज्यीय कानूनों द्वारा उत्तराधिकार उपचारों के होते हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का यह निवासी है, उसके संकेत प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला उस कार्रवाई के नोटिस को प्राप्ति को तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक जिस कार्रवाई के कारण ऐसा कर लगाय जाता है जो करार के अनुसार नहीं है।

2 यदि सम्म प्राधिकारी को आपति उचित प्रतीत होगी और यदि वह स्वयं कोई उर्युन समाजन निकालने में असमर्थ होगा तो, वह ऐसे फराजान के परिवार की दृष्टि से जो इस कारार के अनुष्य मर्ही है, इसे संविदाकारी राज्य के सत्रन्म प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामते को हन करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार सम्बन्ध कोई भी कारार व्यार्थित किया जाएगा जाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी सम्पर्कीय विचार न हो।

3. इस कारार की व्यवस्था करने वाले इसे लागू करने में धरि कोई कठिनाईया व्यववाधिकारी उत्पन्न हों, तो संविधानकारी राज्यों के संघम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयत्न करें। ये उन मामलों में दौहरे कानून के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी कागड़ में व्यवस्था महीं है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अधिग्राम से किसी करार पर पहुँचने के प्रयोगार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पूर्व व्यवहार कर सकते हैं। जब सहमत होने के लिए विवारों का सौचिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के साध्यम से किए जा सकते हैं, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

भारतीय 25

सूचना का प्रादान-प्रदान

1. संविधानार्थी राज्यों के सभी प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें वस्तुतावेज भी शामिल हैं) का धारान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उप-3121 GI/88—2

बंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित मान्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वयित करने के लिए प्रावधारण हैं, जो इस करार के अन्तर्गत आते हैं, जहाँ तक कि इनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष इप से ऐसे करों की आलसाजी अथवा अपवृच्ण को रोकने के लिए करार के प्रतिकूल नहीं हो। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार मुक्त भानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि सूचना भैंजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो, उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा और उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा प्रधियोजन के संबंध में अथवा उनमें पवित्रित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बन्ध हों, जो करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे परियोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यालयी अंदरा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सभी प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित सम्बुद्धि भांति, प्रतिवेद और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहाँ कहीं उपयुक्त हो, कर अपवृच्ण के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना प्रथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा मामलों-विशेष के सुवर्धे में अनुरोध करने पर अथवा दोनों दिशियों में किया जा सकेगा। संविवाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी समय-समय पर, ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची से सहमत होंगे, जिन्हें नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैरग्राफ 1 के उपर्युक्तों का शर्य किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डासना मही होगा :

(क) उस अधिवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों प्रथमा प्रशासनिक प्रथा से हट्टर प्रशासनिक उपाय करता;

(अ) ऐसी सूचना अथवा वस्तुविज्ञानों की सम्पर्क करना जो उस अथवा पूर्वसे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की भाषामत्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना अथवा वस्तुओं की संख्या करना जिसे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, शौदोगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी युक्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो यिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद २६

राजनीतिक श्रीर कौसली कार्यक्राम

इस कारार की किसी भी भाव से राजनीतिक काँसली अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के भर्तरीत भ्रष्टवा विशेष करारों के उपर्योगों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ ୬

मन्त्रिम् उपवस्तु

અનુચ્છેદ 27

प्रवर्त्तन

प्रथेक मनिवाकारी राज्य दूसरे राज्य की इस करार को लागू करने के लिए इसके कानूनों द्वारा भ्रष्टेक्षित कार्यविधि की समाप्ति को अधिसूचित करेगा। यह करार इन अधिसूचनाओं में से आद वाली अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और तपश्चात् निम्नलिखित पर प्रवत्त होगा:

(क) भारत में, जिस केंद्रीय वर्ष में बाब वाली प्राधिकृति थी जाती है, उस वर्ष में परवर्ती भवेत के प्रयम दिन को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ती किसी वर्ष में उद्भूत आय के सम्बन्ध में;

(ख) नेपाल में, जिस केंद्रीय वर्ष में बाब वाली प्राधिकृति थी जाती है, उस वर्ष के भ्रग्गे परवर्ती नेपाली वित्तीय वर्ष के प्रब्रह्म दिन को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में।

प्रकाशन 28

समाप्ति

यह कशार प्रतिविवत भाल तक लाभ रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इसके लाभ होने की तारीख से पाँच वर्ष की अधिक की समाप्ति के पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी भी केंद्रीय वर्ष में जून के तीसरे दिन को या उससे पहले, राजनीतिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को, समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा, और ऐसी स्थिति में यह कशार निम्नलिखित के सम्बन्ध में विष्वायी हो जाएगा :

(क) भारत में, जिस केंद्रीय वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उस वर्ष के भ्रग्गे परवर्ती भवेत के प्रब्रह्म दिन को अथवा उसके बाब प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में;

(ख) नेपाल में, जिस केंद्रीय वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, उस वर्ष के भ्रग्गे परवर्ती नेपाली वित्तीय वर्ष के प्रब्रह्म दिन को अथवा उसके बाब प्रारंभ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में।

जिसके साक्षर में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत प्रधोहस्ताक्षरियों ने इस कशार पर हस्ताक्षर किए हैं।

काठमाडौं में वर्ष एक हजार और सो सतासी के जनवरी मास के प्राचारको दिन को हिन्दी, नेपाली और अंग्रेजी भाषाओं में, वो प्रतिवों में दिया गया। आठवा में भिजता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रधावी होगा।

भारत गवर्नरच्यु की सरकार
की ओर से

नेपाल के वी. के. सरकार
की ओर से

(नारायण बहु विकारी)
विवेग भंडी

(जैमेन्ट कुमार उपाध्याय)
परराम्भ तथा मूमिनुद्धार मंत्री

[प. 8138-का. स. 11/4/89-एफ. टी. डी.]
पी. के. अध्यात्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 5th December, 1988

INCOME-TAX

NOTIFICATION

G.S.R. 1146(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and His Majesty's Government of Nepal for

the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on 1st November, 1988, on the notification by both the Contracting States to each other, under Article 27 of the said Agreement, of the completion of procedures required under their respective laws for bringing the Agreement into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND HIS MAJESTY'S GOVERNMENT OF NEPAL FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and His Majesty's Government of Nepal.

Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income:

Have agreed as follows:

CHAPTER I SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a) in the case of India:

(i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964); (hereinafter referred to as "Indian tax")

(b) in the case of Nepal:

(i) income-tax imposed under the Income-Tax Act, 2031 (hereinafter referred to as "Nepal tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantial similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

CHAPTER II
DEFINITIONS
Article 3
GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Nepal, as the context requires;
- (b) the term "tax" means Indian tax or Nepal tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (c) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit, under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Nepal, His Majesty's Government, Ministry of Finance or their authorised representative;
- (g) the term "national" means by any individual, possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State;
- (h) the term "international traffic" means any transport by an aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State in which his economic activities are concentrated;
- (b) if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State in which his economic activities are concentrated;
- (d) in case of dispute, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a building site or construction or assembly project, but only where such site, project or activity continues for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period;

(h) the furnishing of services by an enterprise through employees or other personnel, where activities continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period.

3. Notwithstanding the preceding provisions of the Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of an activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, a general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. (a) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions, expenses of the enterprise which are incurred for the purpose of the permanent establishment, including only those executive and general administrative expenses incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or

elsewhere which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(b) However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards re-imbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments, in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment of amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees, or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on monies lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary, the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income/profits

derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State, and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least ten per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected

to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 13, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, not subject the company's undistributed profit, to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

Provided, however, that where the interest is paid to a bank carrying on bona fide banking business, which is resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or

not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 13, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICAL 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for the radio

or television broadcasting any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 13, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived

from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 14

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 15, 16, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad an aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 15

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 16

INCOME-EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 13 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artists or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. While income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 13 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 13 and 14, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

ARTICLE 17

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
 - (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who
 - (i) is a national of that State, or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
 - (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is resident of, and a national of that other State.
3. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

ARTICLE 18

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 17, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth

ARTICLE 19

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding Rs. 18,000 (Indian currency), or its equivalent in Nepalese currency during any "previous year" or the "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 20

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this article and article 19, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

ARTICLE 21

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 13, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV

METHODS OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

ARTICLE 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement. Where income is subject to tax in both Contracting States relief from double taxation shall be given in accordance with this Article.

2. Subject to the provisions of the law of Nepal regarding the allowance as a credit against Nepal's tax of tax payable in a territory outside Nepal (which shall not affect the general principle hereof) Indian tax payable under the law of India and in accordance with the provisions of this Agreement whether directly or by deduction, on income from sources within India shall be allowed as a credit against any Nepal tax computed by reference to the same items of income by reference to which the Indian tax is computed.

3. For the purpose of the credit referred to in paragraph (2), the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which tax has been reduced by the special incentive measures under —

(i) Sections 10(4), 10 (4A), 10 (6) (viiA), 10 (15) (iv), 10 (28), 10A, 32A, 33A, 80HH, 80HHA, 80-I and 80-L of the Indian Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and

(ii) any other provision which may subsequently be enacted granting a reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development.

4. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof) Nepal tax payable under the law of Nepal and in accordance with the provisions of this Agreement whether directly or by deduction, on income from sources within Nepal shall be allowed as a credit against any Indian tax computed by reference to the same items of income by reference to which Nepal tax is computed.

Provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Nepal, so however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

5. For the purpose of paragraph (4) of this Article the term "Nepal tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Nepal tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

(a) sub-section (2) of section 42 of the Nepal Income-tax Act, 2031 (1974), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or

(b) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

6. Where under this Agreement a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first mentioned Contracting State may in calculating tax on the remaining income of that person apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with the Agreement had not been so exempted.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
ARTICLE 23
NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

ARTICLE 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or the other Contracting State;

(c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 26

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreement.

CHAPTER VI-

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 27

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedure required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;
- (b) in Nepal, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of Nepalese fiscal year next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

ARTICLE 28

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before

the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect.

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in Nepal, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of Nepalese fiscal year next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Kathmandu on this eighteenth day of January, ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN A.D. in Hindi, Nepali and English languages all the texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA
(NARAYAN DATT TIWARI)
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

GOVERNMENT OF NEPAL
FOR HIS MAJESTY'S
(SHAILENDRA KUMAR UPADHYAYA)
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
AND LAND REFORMS
GOVERNMENT OF INDIA

[No. 8198] F. No. 11|4|69-FTD]
P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

